Renovation and modernisation schemes for Thermal Power Station

*186. SHRI SHANKER SINH VAGHELA:†

SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether a centrally sponsored renovation and modernisation scheme is being implemented in 33 thermal stations to improve their performance; if so, what are the statewise names and locations of the power stations; and

(b) how much amount under this scheme has been spent upto 30th June, 1987 in each case and with what results?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) An Annexure giving the information required is annexed. (*See* below). The renovation & modernisation programme is still under implementation and the results achieved at various thermal stations will be known after the schemes have been completed.

Annexure

Statewise details of Thermal Stations and expenditure incurred on Renovation and modernisation scheme uptill June, 1987

(Rs. in lakhs)

S. No.	Thermal Station	Expenditure incurred upto June, 1987.
1	2	3
1	NTPC	
	(i) Badarpur	721.80
2	DESU	
	(i) Indraprastha	337.87
3	HSEB	
	(i) Faridabad	1142.12
	(ii) Panipat	708.64
4	PSEB	
	(i) Bhatinda	3608.98
5	UPSEB	
	(i) Panki	1598.96
	(ii) Obra	1409.92
	(iii) Harduaganj	2854.51

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shanker Sinh Vaghela.

1	2	3
6	MPEB	
	(i) Korba	450.90
	(ii) Amarkantak	85.97
	(iii) Satpura	1798.79
7	GEB	
	(i) Gandhinagar	1472.82
	(ii) Dhuvaran	877.62
	(iii) Ukai	660.72
8	MSEB	
	(i) Koradi	969.09
	(ii) Nasik	414.20
	(iii) Bhusawal	44.72
	(iv) Paras	33.34
9	APSEB	
	(i) Kothagudem	3083.31
10	TNEB	
	(i) Eanore	6063.21
	(ii) Tuticorin	654.68
11	NLC	
	(i) Neyveli	137.27
12	OSEB	
	(i) Talcher	1027.67
13	DVC	
	(i) Chandrapura	986.50
	(ii) Bokaro	475.36
	(iii) Durgapur	511.06
14	BSEB	
	(i) Patratu	1196.04
	(ii) Barauni	430.17
	(iii) Karabigahia	370.36
15	WBSEB	
	(i) Santaldih	851.11
	(ii) Bandel	485.33
16	DPL	
	(i) Durgapur	679.63
17	ASEB	
	(i) Namrup	622.88

श्री शंकर सिंह वाघेला : मैडम डिप्टी चेयरमैन, अभी हमारे मंत्री साठे जी भेल के बारे में बता रहे थे मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पूरे देश में कोई भी थर्मल पावर स्टेशन रेनोवेशन और माडर्नाइजेशन के अलावा बचा है और जहां वे यंत्र लगे हैं वह भेल के अलावा और कोई इम्पोर्टेड यंत्र लगे हैं यह बताएं ?

श्री वसंत साठे : जहां तक ये बहुत से स्टेशन्ज हैं उसमें ज्यादातर इक्विपमेंट बल्कि प्राय: सभी हिन्दुस्तानी ही बने हुए हैं, उसमें बी० एच० ई०ए ल० ए० बी० एल० और आयल के ऐसे यूनिटस के बनाए हुए इक्विपमेंट हैं। कुछ पुराने हैं और कुछ अभी चन्द साल पहले लगे हैं और हर प्लांट में रेनोवेशन तथा माडर्नाइजेशन यह कंटीन्युअस प्रोसेस होता है। वह हमेशा चालू रखना चाहिए जैसे अपनी गाड़ी को हमेशा ठीक रखना पड़ता है उसी तरह से इक्विपमेंट की बात है और वह रखना चाहिए तभी वह इक्विपमेंट ठीक चलता है और उसका उत्पादन भी अच्छा रहता है।

श्री शंकर सिंह वाघेला : मैडम डिप्टी चैयरमैन, यह भेल को बचाने की खवामखाह कोशिश कर रहे हैं। पूरे पब्लिक एंटरप्राइजेज स्टेट के कंट्रोल में है इसमें सब से ज्यादा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लास कर रहा है। कोई राज्य नहीं बचा होगा जिसने भेल के यंत्रों के बारे में कंप्लेंट नहीं की हो। मैं माननीय मंत्री जी से दूसरी बात करता हूं कि जब भेल फेल है तो आप क्या प्राइवेट मैनेजमेंट के लिए सोच रहे हैं ? दूसरा यह थर्मल पावर जेनरेशन में अगर प्राब्लम होती है तो गैस हाइड्रो इलैक्ट्रिक एटामिक एनर्जी जिसके बारे में बहुत बड़ा विवाद है ऐसा सोचकर इस यंत्र को बन्द करके और एन० टी० पी० सी० में भी मेरे ख्याल से आपके इंपोर्ट किए हुए यंत्र हैं तो क्या आप ऊर्जा का स्रोत इस थर्मल के अलावा और हाइड्रो गैस और एटामिक एनर्जी के यह सोच रहे हैं ?

श्री वसंत साठे : मैडम बहुत ही कैम्प्लीकेटेड और विस्तृत सवाल माननीय सदस्य ने पूछ लिया है। यह सारा विचार किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य यह है कि देश में जो संयंत्र लगे हैं वह ठीक चलें और अन्त में हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा इस देश में निर्माण कर सकें, इन सब चीजों का जो-जो आपने सुझाया उन पर विचार बराबर और अवश्य किया जा रहा है।

श्री प्रमोद महाजन : उपसभापति महोदया, ताप विद्युत केन्द्रों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण कार्य का कार्यान्वयन अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है, इस पृष्ठ भूमि में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम सरकार ने कब शुरू किया ? इसे पूर्ण करने के लिए कितनी कालावधि सोची गयी थी ? इसके लिए केन्द्र ने कितनी धनराशि निर्धारित की थी? अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ? क्या कुछ राज्य बिजली बोर्ड ऐसे हैं जिन्होंने निर्धारित धनराशि से कम खर्च की है? क्या कुछ राज्य बिजली बोर्ड ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मशीन के आर्डर तक बुक नहीं किए हैं, अगर ऐसे हों तो उनके नाम बताएं और क्या सरकार इसकी गति से संतुष्ट है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : महोदया, मैं यह मानती हूं कि जो इसका क्रियान्वयन जितनी तीव्र गति से सम्पादित करना था, वह नहीं हुआ है लेकिन इसके कुछ कारण हैं। वर्ष 1984-85 में योजना बनायी गयी थी और योजना बनाते समय सोचा गया था कि तीन-चार वर्ष में इसका कार्य पूरा हो सकेगा। परन्तु इस कार्य के लिए सबसे आवश्यक था कि पहले सी०ई०ए० के इंजीनियर्स वहां जाकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ बैठकर यह देखें कि कौन-कौन से यूनिट ऐसे है जिनमें कि आधुनिकीकरण, नवीनीकरण की आवश्यकता प्रतीत होती है और उसके आधार पर उस तरह की योजना बनाएं। इस योजना के लिए 34 प्रकार की योजनाएं बनायी गयी हैं 162 यूनिटस के लिए। इस पर अभी तक जो 500 करोड़ रुपए केन्द्र के द्वारा रखे गए थे और बाकी राज्यों द्वारा 400 करोड़ के लगभग रखे गए थे, उसमें से केन्द्र से 192 करोड़ रुपए का धन खर्च हो चुका है और राज्यों के द्वारा 206 करोड़ का खर्च कराया गया है हमें आशा है कि जहां-जहां यह कार्य सम्पादित हो चुका है पूरी तरह से या आधा-अधूरा भी जैसे कि भटिंडा में, एन्नोर में कोठागुडम में फरीदाबाद में, हरदुआगंज में जहां भी थोड़ा-बहुत इसका आधुनिकीकरण-नवीनीकरण हुआ है, वहां बड़ी सफलता मिली है

और आशा है कि यह कार्य 3-4 साल में पूरा होगा और इससे बड़ा लाभ होगा।

श्री प्रमोद महाजन: मैंने उन बिजली बोर्डस के नाम पूछे थे जिन्हें कि आपने राशि दे दी है लेकिन उन्होंने खर्च नहीं की है। उसके साथ ही मैंने यह भी पूछा था कि जिस प्रकार कुछ राज्य बिजली बोर्ड ऐसे है कि they have not even placed orders. तो आपका रिनोवेशन होगा क्या।

श्रीमती सुशीला रोहतगी: सब राज्यों में बिजली बोर्ड्स ने अपने टास्क फोर्स बनाए हैं और यह उनका कार्य है कि वे देखें कि क्या आर्डर प्लेस करने हैं और वे करें। हमारी यह सूचना है कि टास्क फोर्स ने कुछ राज्यों में अपना कार्य पूरा किया है और हम यह चाहते हैं कि दूसरे राज्यों में भी ऐसी सफलता प्राप्त की जा सके। जहां पर पूरी तरह सफलता नहीं मिली है, उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। हमारी सूचना के आधार पर सब जगह टास्क फोर्स काम कर रहे हैं।

SHRI K. MOHANAN: Madam, of course, this is regarding renovation and modernisation of the existing projects. If you permit me, I want to ask this. This year we are facing unprecedented drought. In the States which are solely depending on hydro-electric projects, what is the proposal on the part of the Government to set up new thermal plants? Is there any proposal from the Government of Kerala regarding this? Has the Government taken any decision or at what stage is it there now?

I do not know whether it is connected with this. Because of the seriousness of the problem, I have asked this.

SHRI VASANT SATHE: One thing, I would like to say. We are fully aware that in the present drought situation throughout the country there may be tremendous burden on the requirement of power, particularly thermal power because for want to rain it will be the hydel power which will get affected. Therefore, this renovation and modernisation is one of the most important and essential features to see that our State Electricity Board units, thermal units, operate and run well.

As far as Kerala or other States where there is paucity of power are concerned, today immediately if you want to set up a statios, it takes five years. That will not be relevant as far as the present drought that we are facing is concerned.

SHRI K. MOHANAN: In the coming years also we are going to face this.

SHRI VASANT SATHE: But as a permanent measure, we have approved a scheme of thermal stations in Kerala. The question of feasibility, economics, weather, bringing of coal etc., all those questions are being examined. Even atomic energy question is being considered. So, we are in favour of establishing thermal units in areas which have to depend more or less only on hydel power so as to restore the balance.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Can you permit me to ask a specific clarification from the Minister regarding a thermal power plant in Durgapur, which was on fire several years back? May be the Minister will be remembering our representation to him. A thermal unit was on fire a committee was appointed and there was a strong suspicion that the fire was due to mismanagement or the part of those who managed the unit. I would like to know whether that particular thermal unit at Durgapur under DVC that caught fire some years back is being renovated, if that renovation programme is being carried out in accordance with the recommendation of the inquiry committee if that inquiry committee has submitted any report and if no renovation is being done, why not?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Madam, you would agree that this requires a separate notice. But at the same time I would like to emphasise that we are giving topmost importance to this renovation and modernisation programme because we feel, when this programme is completed in the course of three or four years, we will be able to get an additional... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: She has asked you to give a separate notice for

this question. Other things which you asked... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: (*Interruptions*) I have been meeting her on several occasions.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: When this programme is completed and schemes are carried out, we shall get an additional 1400 megawatts. That itself shows the importance of this renovation and modernisation. And the plant-load factor will rise from 46 per cent on average to 53 per cent. Therefore, we are very very keen, whether it is Durgapur, whether it is any State or any unit, that it comes up in the shortest possible time.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I would like to know from the hon. Minister whether thermo electric precipitators have been installed in all the existing thermal plants to check pollution.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: No. It will take a little time. They have been ordered in many places. It takes normally about a year or year and a half. Once it is put up, we find there is a lot of improvement in the performance. That will just take a little time. Therefore, orders are being issued.

श्री बीरभद्र प्रताप सिंह : महोदया, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तीन थर्मल पावर स्टेशनों—कोरबा, ओबरा और हरदुआगंज—को ही माडर्नाइजेशन के लिए लिया गया है और पूर्वांचल को क्यों इससे वंचित कर दिया गया है ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि महोली और मउनाथभंजन के प्लांट भी बन्द हो गए हैं और पूरा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया गया है । तो मैं जानना चाहूंगा कि कोई गाइड लाइन आपने राज्य सरकारों को दी हैं या खुद उन्होंने इनका माडर्नाइजेशन किया है जिससे कि उत्तर प्रदेश का पूरा पूर्वांचल छोड़ दया गया है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : महोदया, समें किसी को छोड़ने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता । पूर्वांचल की ओर समय-समय पर ध्यान दिया जा रहा है और देना भी चाहिए । ये तीन प्लांट जो लिये गये हैं वे इस आधार पर लिय गए हैं कि उनका कार्य ठीक नहीं चल रहा था । उनका नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करने से वहां प्रगति हो सकती है । इसलिए इन तीनों को चुना गया है । इस कार्य से आशा है कि ये तीनों ठीक से काम करेंगे ।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : उपसभापति महोदया, इस सवाल के जवाब में लिखा है कि अलग-अलग बिजली घरों के लिए नूतनीकरण और आधुनिकीकरण में कुछ राशि रखी है । महाराष्ट्र स्टेट में चार बिजली घर हैं । इनमें से कुछ के लिए आपने पैसे रखे हैं । मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि नूतनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए वहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट लेबोरेट्रीज हैं । अगर हैं तो आधुनिकीकरण और नूतनीकरण के बाद पावर जनरेशन में, उनकी एफिशियेंसी में कुछ बढ़ोतरी हुई है या नहीं ? अगर हुई है तो कितनी हुई है, यह बताने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैंने शुरू में 3, 4, 5 स्टेशनों का जिक्र किया जहां पर थोड़ा बहुत कार्य सम्पादन हुआ और जहां पर सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा । यह सही है कि जहां-जहां जाइये, चाहे महाराष्ट्र में जाइये चाहे कहीं किसी और प्रदेश में जाइये जहां यह यूनिट होगी और जहां यह काम होगा वहां पर अवश्य काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा । भटिंडा के बारे में कहना चाहती हूं कि जब कार्य शुरू हुआ था, पी० एल० एफ० उस समय 50 था जब थोड़ा इम्प्लीमेंट हुआ वहां पर 61 परसेंट हो गया है । एन्नोर जो तमिलनाडु में है 34 से 50 परसेंट सुधार हुआ है, कोठागुडम जो आन्ध्र प्रदेश में है 35 से 54 परसेंट पी० एल० एफ० बढ़ा है । फरीदाबाद में 32 से 45 परसेंट, हरदुआगंज में 36 से 50 परसेंट हुआ है जबकि पूरा कार्य अभी सम्पादन नहीं हुआ । मुझे आशा है कि इस प्रकार और भी हैं ।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : मेरा प्रश्न महाराष्ट्र के बारे में था कि कितना सुधार हुआ है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : अभी महाराष्ट्र का नहीं है ।

DR. H. P. SHARMA: Madam Deputy Chairman, one of the major hurdles in augmenting the power picture of the country and as has been accepted by the Government on several occasions is the lack of control or coordination between the Centre and State Electricity Boards. Madam, my question relates to the allocation of responsibility. This ambitious programme of renovation is going to cost the Government some Rs. 400 crores or more. May I know from the Minister who is financing this programme? Is it borne entirely by the Central Government or it is divided between the Centre and the States? Or the Centre is bearing the financial burden and the State Electricity Boards are handling the work of renovation?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Madam, I think the hon. Member has put a very pertinent question and coordination is an essential part of the entire activity and for his information, I would like to say that C.E.A. has been doing the overall coordination and monitoring of the implementation of renovation and modernisation programme. But these activities are being executed by the concerned State Electricity Boards. Besides this, a Steering Committee has been set up in the Department of Power under the chairmanship of Secretary for overall supervision, monitoring and expediting the implementation of the programme. The representatives of the Central Electricity Authority, Ministry of Industry, Planning Commission, BHEL, DGTD are members of the Steering Committee. Therefore, this coordination aspect is being looked after by them.

DR. H. P. SHARMA: They go on sitting in that Committee, but actually the State Electricity Boards are not prepared to listen to the Committee. What is the Government going to do about it?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: They are not only sitting in the Committee meeting but every month and every fortnight at the level of Secretaries even at the Ministerial level, the work carried out is being monitored. We are fully posted with the work and from time to time we see that the work should be expedited.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 187.

Construction of Bakreswar Thermal Plant

*187. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state by when the construction of Bakreswar thermal plant is likely to commence?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): The proposed Bakreswar Thermal Power Project in West Bengal could be taken up for implementation after the funds required have been tied up and investment approval has been accorded.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam Deputy Chairman, Government has acquired the latest technology with regard to answering questions, that is, by not answering questions. My specific question to the Ministry is this: I complained of inordinate delay in the sanction of Bakreswar Thermal Power project for West Bengal. I do not know whether it is a political discrimination. This Government is sitting over this project. May I know from the Minister specifically, how long they will take to finalise this project and how long they will take to start the implementation of the project? Madam, as you know, the country is suffering from acute power shortage.

SHRI VASANT SATHE: I have totally refuted the allegation that there is any delay on our part. Madam, actually this is a State project and they wanted to set up a project of about 630 MW which would require about Rs. 700 crores. They did not have the money. They came to